

चुनावी बांड

सिलेबस: जीएस पेपर-II (पारदर्शिता और जवाबदेही, सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप)

संदर्भ: चुनावी बांड (ईबी) के माध्यम से राजनीतिक दलों को दान 10,000 करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर गया है।

चुनावी बांड (EB) के बारे में

- एक चुनावी बांड एक वित्तीय उपकरण की तरह है जिसका उपयोग राजनीतिक दलों को दान देने के लिए किया जाता है। जनता योग्य राजनीतिक दलों को निधि देने के लिए इन बांडों को भी जारी कर सकती है।
- ये बांड बैंक नोटों के समान भूमिका निभाते हैं जो वाहक को ब्याज और मांग से मुक्त देय होते हैं।
- एक व्यक्तिगत पार्टी इन बांडों को डिजिटल रूप से या डीडी या चेक की मदद से खरीद सकती है।
- चुनावी बांड योजना को केंद्र सरकार द्वारा 2018 में लॉन्च किया गया था।

कामचलाऊ











- ये बांड बिना किसी अधिकतम सीमा के 1,000 रुपये, 10,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 10 लाख रुपये और 1 करोड़ रुपये के गुणकों में जारी किए जाते हैं।

जु भारतीय स्टेट बैंक इन बांडों को जारी करने और भुनाने के लिए प्राधिकृत है, जो जारी किए जाने की तारीख से पंद्रह दिनों के लिए वैध हैं।

- ये बांड केवल एक पंजीकृत राजनीतिक दल के नामित खाते में भुनाने योग्य हैं।
- बांड भारत के किसी भी नागरिक द्वारा जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीनों में प्रत्येक में दस दिनों की अवधि के लिए खरीद के लिए उपलब्ध हैं, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।
- एक व्यक्ति एक व्यक्ति होने के नाते बांड खरीद सकता है, या तो अकेले या संयुक्त रूप से अन्य व्यक्तियों के साथ।

ईबी की शुरूआत के पीछे तर्क

- भारत में चुनावी वित्तपोषण में पारदर्शिता लाने के लिए चुनावी बांड योजना के पीछे केंद्रीय विचार।
- केंद्र सरकार की राय में चुनावी बांड चुनावों के वित्तपोषण के लिए काले धन के उपयोग पर एक नज़र रखेंगे।
- सरकार ने इस योजना को "कैशलेस-डिजिटल अर्थव्यवस्था" की ओर बढ़ने वाले देश में "चुनाव सुधार" के रूप में वर्णित किया था।
- बांड पर दाता का नाम नहीं बताया गया है।
- चुनावी बांड की खरीद के माध्यम से राजनीतिक दलों को 20,000 रुपये से कम का योगदान करने वाले दानदाताओं को पैन आदि जैसे अपनी पहचान का विवरण प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है।
- चुनावी बांड के अभाव में, दानदाताओं के पास अपने व्यवसायों से पैसे निकालने के बाद नकद द्वारा दान करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा, सरकार ने कहा।

	What are Electoral Bonds? <ul style="list-style-type: none"> • A way to donate to Political Parties • Similar to demand draft, but solely for donation to political parties. • Bears name of the party that donor donates to, NOT name of donor 		How to purchase EBs: <p>Bonds issued in multiples of ₹ 1000, 10000, 1 Lakh and 1 crore</p> <p>purchasable at</p> <p>Authorized SBI branches; buy with cheque/digital payment (NO CASH)</p> <p>KYC details of buyer are collected by bank, but remain confidential</p> <p>Buyers purchase bonds bearing ONLY party name, NOT buyer's name</p> <p>EB physically handed over to party</p> <p>Donation to regd. parties with >1% vote share in last Lok Sabha/State Assembly election</p> <p>Bonds must be encashed within 15 days of receipt</p> <p>Bonds redeemable ONLY in authorized SBI account notified to EC</p>
	Who can buy EBs? <ul style="list-style-type: none"> • Any Indian citizen • Any body incorporated in India i.e. All private, public, one-person companies based in India • Indian subsidiaries of foreign companies (but NOT foreign companies) 		
	Who can receive EBs? <ul style="list-style-type: none"> • Any Political Party with >1% votes in previous Lok Sabha/State Assembly Elections • One SBI bank account must be specified to receive EBs; Election Commission (EC) must be notified 		
	When can EBs be purchased? <p>In a 10-day period in the beginning of each quarter i.e. 1 - 10 January 1 - 10 April 1 - 10 July 1 - 10 October</p>		
	Where can EBs be purchased? <p>At 29 authorised State Bank of India branches* across India. Account holders and non-holders with SBI can purchase bonds on supplying KYC details</p>		

आलोचना

इसके मूल विचार का खंडन:


- चुनावी बांड योजना की केंद्रीय आलोचना यह है कि यह चुनावी वित्त पोषण में पारदर्शिता लाने के लिए जो कुछ भी करना था, उसके ठीक विपरीत करता है।

उदाहरणके लिए, आलोचकों का तर्क है कि चुनावी बांड की गुमनामी केवल व्यापक जनता और विपक्षी दलों के लिए है।

जबरन वसूली की संभावना:

तथ्य यह है कि इस तरह के बांड एक सरकारी स्वामित्व वाले बैंक (एसबीआई) के माध्यम से बेचे जाते हैं, सरकार के लिए यह जानने के लिए दरवाजा खुला छोड़ देता है कि उसके विरोधियों को कौन वित्त पोषित कर रहा है।

Benefits of Electoral Bonds



<p>WILL BRING substantial transparency in political donations against the present system of contributions in the election funding mechanism</p>	<p>HOW MUCH funding comes, what kind of funding it is, the source of funding and where it will be spent will be known clearly</p>
<p>NON DISCLOSURE of recipients will ensure people are free to donate to any political party of their choice</p>	<p>WILL REINFORCE the idea of moving away from a cash system towards clean money which cheque system could not achieve</p>
<p>15 DAYS between buying and selling will ensure they don't turn into a parallel economy</p>	

- यह, बदले में, **दिन की सरकार के लिए संभावना को या तो पैसे निकालने की** अनुमति देता है, विशेष रूप से बड़ी कंपनियों से, या सत्तारूढ़ पार्टी को वित्त पोषित नहीं करने के लिए उन्हें पीड़ित करने के लिए - किसी भी तरह से सत्ता में पार्टी को अनुचित लाभ प्रदान करना।

लोकतंत्र के लिए एक झटका:

- वित्त अधिनियम 2017 में संशोधन के माध्यम से, केंद्र सरकार ने राजनीतिक दलों को चुनावी बांड के माध्यम से प्राप्त दान का खुलासा करने से छूट दी है।
- इसका मतलब है कि मतदाताओं को यह नहीं पता होगा कि किस व्यक्ति, कंपनी या संगठन ने किस पार्टी को वित्त पोषित किया है, और किस हद तक।
- हालांकि, एक प्रतिनिधि लोकतंत्र में, नागरिकों ने उन लोगों के लिए अपना वोट डाला जो संसद में उनका प्रतिनिधित्व करेंगे।

जानने के अधिकार से समझौता करना:

- भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने लंबे समय से कहा है कि "**जानने का अधिकार**" विशेष रूप से चुनावों के संदर्भ में, भारतीय संविधान के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार (अनुच्छेद 19) का एक अभिन्न अंग है।

स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के खिलाफ:

- चुनावी बांड नागरिकों को कोई विवरण प्रदान नहीं करते हैं।
- उक्त गुमनामी उस समय की सरकार पर लागू नहीं होती है, जो हमेशा भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से डेटा की मांग करके दाता के विवरण तक पहुंच सकती है।
- इसका तात्पर्य यह है कि सत्ता में सरकार इस जानकारी का लाभ उठा सकती है और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों को बाधित कर सकती है।

क्रोनी पूंजीवाद:

- चुनावी बांड योजना राजनीतिक दान पर सभी पहले से मौजूद सीमाओं को हटा देती है और प्रभावी रूप से अच्छी तरह से संसाधन वाले निगमों को चुनावों को निधि देने की अनुमति देती है, बाद में क्रोनी पूंजीवाद के लिए मार्ग प्रशस्त करती है।

परिवार न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2022

सिलेबस: जीएस पेपर-II (परिवार न्यायालय अधिनियम)

राज्यसभा ने परिवार न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2022 को ध्वनिमत से पारित कर दिया।

इस विधेयक में हिमाचल प्रदेश और नागालैंड में स्थापित परिवार न्यायालयों को सांविधिक कवर प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।

प्रमुख संशोधन

- **धारा 1 की उप-धारा 3:** विधेयक में धारा 1 की उप-धारा 3 में 15 फरवरी, 2019 से हिमाचल प्रदेश और 12 सितंबर, 2008 से नागालैंड में परिवार न्यायालयों की स्थापना के लिए प्रावधान करने के लिए एक प्रावधान शामिल करने का प्रयास किया गया है।
- **धारा 3ए:** यह हिमाचल प्रदेश और नागालैंड की सरकारों और इन राज्यों के परिवार न्यायालयों द्वारा किए गए अधिनियम के तहत किए गए सभी कार्यों को पूर्वव्यापी रूप से मान्य करने के लिए एक नई धारा 3 ए भी सम्मिलित करने का प्रयास करता है।
- **पूर्वव्यापी प्रभाव:** दोनों राज्यों में परिवार न्यायालयों की स्थापना इन तारीखों से पूर्वव्यापी रूप से मान्य होगी।
- दोनों राज्यों में अधिनियम के तहत की गई सभी कार्रवाइयों, जिसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति और परिवार न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों और निर्णयों को शामिल किया गया है, को भी इन तिथियों से पूर्वव्यापी रूप से वैध माना जाएगा।

परिवार न्यायालय अधिनियम 1984

परिवार न्यायालयों की स्थापना:

- परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 को परिवार न्यायालयों की स्थापना के लिए अधिनियमित किया गया था ताकि सुलह को बढ़ावा दिया जा सके और विवाह और पारिवारिक मामलों से संबंधित विवादों का त्वरित निपटान सुनिश्चित किया जा सके और संबंधित मामलों के लिए।

न्यायाधीशों की नियुक्ति:

- राज्य सरकार, उच्च न्यायालय की सहमति से, एक या अधिक लोगों को परिवार न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त कर सकती है।

एसोसिएशन ऑफ सोशल वेलफेयर एजेंसियां:

- राज्य सरकार निम्नलिखित का एक परिवार न्यायालय प्रदान कर सकती है:
 - क. सामाजिक कल्याण में लगे संस्थान या संगठन।
 - ख. परिवार के कल्याण को बढ़ावा देने में पेशेवर रूप से लगे हुए लोग।
 - ग. समाज कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्ति।
 - घ. कोई अन्य व्यक्ति जिसका परिवार न्यायालय के साथ जुड़ाव उसे इस अधिनियम के प्रयोजनों के अनुसार अपने अधिकार क्षेत्र का अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग करने में सक्षम बनाएगा।

प्रारंभिक परीक्षा मुख्य तथ्य

हर घर तिरंगा अभियान

- 'हर घर तिरंगा' आजादी का अमृत महोत्सव के तत्वावधान में एक अभियान है जो लोगों को तिरंगा को घर लाने के लिए प्रोत्साहित करता है और भारत की स्वतंत्रता के 75 वें वर्ष को चिह्नित करने के लिए इसे फहराता है।
- स्वतंत्रता के 75 वें वर्ष में ध्वज को सामूहिक रूप से एक राष्ट्र के रूप में घर लाना इस प्रकारन केवल तिरंगा के लिए व्यक्तिगत संबंध के कार्य का प्रतीक बन जाता है, बल्कि राष्ट्र-निर्माण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का एक अवतार भी बन जाता है।
- पहल के पीछे विचार लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना का आह्वान करना और भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना है।

राष्ट्रमंडल खेल

तेजस्विन ने अपनी पहली कोशिश में 2.22 मीटर की दूरी तय करने के बाद कांस्य पदक जीता।

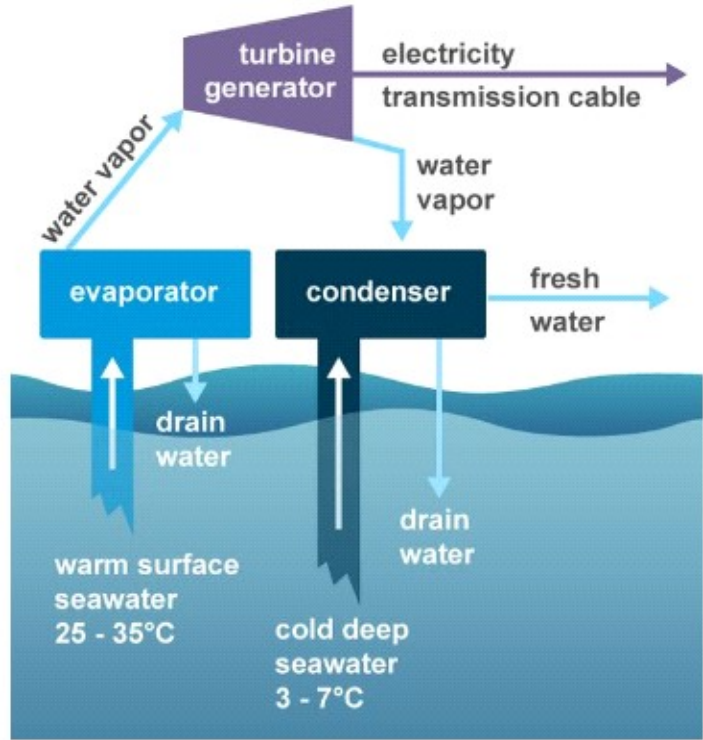
तेजस्विन शंकर का ऊंची कूद में कांस्य पदक भी राष्ट्रमंडल खेल, 2022 में ट्रैक और फील्ड में भारत का पहला है।

- यह एक सदस्य-आधारित संगठन है जो सरकार से कोई धन प्राप्त नहीं करता है और राष्ट्रमंडल खेल के अधिकारियों के साथ-साथ खेल आयोजनों और एथलीटों की भागीदारी को प्रशासित, नियंत्रित और समन्वयित करने के लिए मौजूद है।
- 2022 राष्ट्रमंडल खेलों को आधिकारिक तौर पर **XXII राष्ट्रमंडल खेलों के रूप में जाना जाता है और बर्मिंघम 2022 के रूप में जाना जाता है।**

- 1881 में, **एस्टली कूपर** द्वारा एक खेल आयोजन में कई गेम होने का एक नया विचार पेश किया गया था।
- राष्ट्रमंडल खेलों को **दोस्ताना खेलों** के रूप में भी जाना जाता है।
- राष्ट्रमंडल खेल **चतुष्कोणीय हैं जिसका** अर्थ है कि यह चार साल के लिए आयोजित किया जाता है।
- राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भारतीय टीम में **322 सदस्य होते हैं जिनमें 72 टीम अधिकारी, 26 अतिरिक्त अधिकारी, नौ दल के कर्मचारी और तीन महाप्रबंधक शामिल होते हैं।**

लक्षद्वीप में महासागर थर्मल ऊर्जा रूपांतरण संयंत्र (ओटीईसी)

- राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती में 65 किलोवाट (किलोवाट) की क्षमता के साथ एक महासागर थर्मल एनर्जी रूपांतरण (ओटीईसी) संयंत्र की स्थापना कर रहा है।
- महासागर तापीय ऊर्जा रूपांतरण (ओटीईसी) **समुद्र की सतह के पानी और गहरे समुद्र के पानी के बीच तापमान अंतर (थर्मल ग्रेडिएंट) का उपयोग करके ऊर्जा उत्पादन के लिए एक प्रक्रिया या तकनीक है।**
- सूर्य से ऊर्जा समुद्र की सतह के पानी को गर्म करती है।
- उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, सतह का पानी गहरे पानी की तुलना में बहुत गर्म हो सकता है।
- इस तापमान अंतर का उपयोग बिजली का उत्पादन करने और समुद्र के पानी को विघटित करने के लिए किया जा सकता है।



सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड (सीडीएसएल)

- सीडीएसएल पर सक्रिय डीमैट खातों की संख्या **7 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई।**
- सीडीएसएल की स्थापना 1999 में **सभी बाजार प्रतिभागियों के लिए सस्ती लागत पर सुविधाजनक, भरोसेमंद और सुरक्षित डिपॉजिटरी सेवाओं के लक्ष्य को पूरा करने के लिए** की गई थी।
- निक्षेपागार इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रतिभूतियों को रखने की सुविधा प्रदान करता है।
- एक डीमैट खाता **निवेशकों को इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में शेयर और प्रतिभूतियों को रखने में मदद करता है।**
- सीडीएसएल को बीएसई लिमिटेड द्वारा भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और यूनिजन बैंक ऑफ इंडिया जैसे प्रमुख बैंकों के साथ **मिलकर बढ़ावा दिया गया था।**